वी. आर. कटारकी

बनाम

कर्नाटक राज्य और अन्य

22 मार्च, 1990

[रंगनाथ मिश्रा और के. रामास्वामी, न्यायाधिपतिगण]

सेवा कानूनः कर्नाटक न्यायिक सेवा - सिविल न्यायाधीश - आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में अनियमितताओं के आधार पर बर्खास्तगी - की वैधता - सजा की मात्रा - चाहे आनुपातिक हो-पक्षकारो का विश्वास - न्यायिक प्रणाली की नींव - इसलिए, प्रभावित नहीं होना है।

अपीलार्थी, एक सिविल न्यायाधीश, को उच्च न्यायालय ने इस आधार पर बर्खास्त कर दिया था कि उसने (1) भूमि अधिग्रहण अधिकारी को पत्र लिखकर भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 18 के तहत रेफरेंसो के न्यायनिर्णयन में पंचाट को लागू करने के लिये कुछ अनियमितताएं की थी, भले ही सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 82 के तहत राज्य के खिलाफ आदेश 90 दिनों से पहले निष्पादन के लिए उपलब्ध नहीं थे, (ii) भूमि के लिए वैध से अधिक मूल्यांकन तय करना, और (iii) पक्षकारों के लिए अधिवक्ता द्वारा मुद्रित आदेश-पत्रों का उपयोग करना। उस पर यह भी आरोप लगाया गया था कि उसने उपयुक्त अधिकारियों से पूर्व अनुमति के बिना 1,000 रुपये का एक पंप-सेट खरीदा था। बर्खास्तगी की उसकी चुनौती को न्यायिक पक्ष में उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसलिए, यह अपील है।

अपील को खारिज करते हुए, लेकिन दंड की मात्रा को संशोधित करते हुए, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया:

1.1 यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि न्यायिक अधिकारियो को बोर्ड से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए और न्याय के चैनल को साफ रखना चाहिए। न्यायिक प्रणाली में वादकारी पक्षों का विश्वास ही प्रणाली की नींव है और ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जो उस पर असर पडे। [5 सी]

1.2 मूल्यांकन का निर्धारण एक न्यायिक कार्य है। भले ही न्यायिक प्रक्रिया के एक भाग के रूप में अपील में मूल्यांकन के आकलन को संशोधित या पुष्टि की जाती है, फिर भी मामले की समग्र तस्वीर से देखने योग्य न्यायिक अधिकारी का आचरण अभी भी देखने के लिये उपलब्ध होगा। उचित मामलों में यह न्यायिक कृत्यो से भी निष्कर्ष निकालने के लिए खुला हो सकता है। [3 एफ]

1.3 अभिलेख पर सामग्री पर विचार करने पर, अपीलार्थी के रुख को स्वीकार करने की कुछ गुंजाइश है कि मूल्यांकन तय करने में कुछ गलती हुई है, कोई गलत मकसद नहीं है। इसलिए, वह संदेह का लाभ पाने का हकदार है। हालाँकि, यह नहीं कहा जा सकता है कि पुरस्कारों को लागू करने के लिए पत्र लिखने मे उसने सहज रूप से काम किया था। इसी तरह, उसने एक विशेष अधिवक्ता द्वारा मुद्रित आदेश-पत्रों का उपयोग करने की अनुमति देने में भी अविवेकपूर्ण व्यवहार किया था। चूंकि अपीलार्थी के पास 43 एकड़ कृषि भूमि है, इसलिए बिना पूर्व अनुमति के पंप-सेट की खरीद के बारे में कोई गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। [3 जी-एच, 4 सी, ई, एफ-जी]

1.4 आम तौर पर, अनुशासनात्मक कार्रवाई में दी गई सजा की मात्रा का औचित्य तय करना अदालत का काम नहीं है और ऐसे मौके आये हैं जब इस अदालत

ने सजा की मात्रा पर उच्च न्यायालयो के हस्तक्षेप को अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य माना है। लेकिन आरोपों के अवशेषो को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी को सेवा से बर्खास्त करना अनुपात से बाहर था और अनिवार्य सेवानिवृत्ति न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी। तदनुसार, अपीलार्थी को उसकी बर्खास्तगी के लागू होने की तारीख से अनिवार्य रूप से सेवा से सेवानिवृत्त माना जाएगा। [4 एच, 5 ए-बी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 4392/1986

(रिट याचिका संख्या 19086/1985 में कर्नाटक डच न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 30.1.1986 से)

एम. सी भंडारे, राजेश्वर ठाकुर, रणजी थॉमस और टी. श्रीधरन, अपीलार्थी के लिए ।

महाधिवक्ता बी. बी. आचार्य और पी. आर. रमेश, प्रतिवादीगण के लिये।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

<u>आदेश</u>

अपीलार्थी कर्नाटक न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश था और बीजापुर जिले के बागलकोट में तैनात था। 1979 के कुछ समय बाद, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित अपर कृष्णा परियोजना के प्रयोजनो के लिये 1894 के केंद्रीय अधिनियम 1 के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गई थी और अधिनियम की धारा 18 के तहत रेफरेंस लंबित थे, जो कि अपीलार्थी द्वारा निर्णित किये गये थे। उच्च न्यायालय में कई अनियमितताओं की सूचना पहुँचने के आधार पर, अपीलार्थी के खिलाफ कई आरोपों के साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी, लेकिन मुख्य बाते जिनसे हम संबंधित है वे है : (1) सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 82 में निहित प्रावधान के बावजूद कि राज्य के खिलाफ डिक्री डिक्री बनाने की तारीख से 90 दिनों के लिए निष्पादित करने

के लिए उपलब्ध नहीं थी; भूमि अधिग्रहण अधिकारी को पत्र लिखकर पंचाटो को लागू करने के लिए कदम उठाए गए थे; (2) अपीलकर्ता द्वारा भूमि का वैध मूल्य अधिक निर्धारित किया गया था; (3) न्यायिक कार्यवाही में उपयोग करने के लिए राज्य की कीमत पर प्रदान किए गए आदेश पत्रों के अलावा अन्य मुद्रित आदेश पत्रों का उपयोग भूमि अधिग्रहण मामलों में किया गया था, जहां न्यायालय का नाम इंगित करने के अलावा, अपीलकर्ता के वकील का नाम भी मुद्रित किया गया था। इन तीन आरोपो के अलावा, कई अन्य आरोपी भी शामिल है, जिनमें से एक आरोप यह दर्शाता है कि उन्होने एक पंप सेट और उसके सहायक उपकरण रूपये 1 हजार की कीमत के बिना उपयुक्त प्राधिकारी की पूर्व सहमति के खरीदे थे। अंततः उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है और बर्खास्तगी को दी गई चुनौती को उच्च न्यायालय ने न्यायिक पक्ष से खारिज कर दिया है।

हमने अपील के समर्थन में उपस्थित विद्वान वकील को विस्तार से सुना है। उन्होने हमे तथ्यो के बयानो और जांच प्राधिकरण की रिपोर्ट और अभिलेख पर दिखाई देने वाली कुछ अन्य सामग्रियो सहित आरोपो के बारे में बताया है। जहां तक मूल्यांकन पहलू का सवाल है, हम पाते है कि शामिल 17 मामलो में से जहां उच्च मूल्यांकन दिया गया था, तीन मामलो में राज्य अपील मे गया था। लेकिन उच्च मूल्यांकन की दलील पर अपील में कोई चुनौती नहीं उठाई गई थी। तीन अपीले पहले ही खारिज कर दी गई है और न्यायालय के निर्णयो की पुष्टि कर दी गई है। शेष मामलो के सबंध में हमे अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि मूल्यांकन में संशोधन के साथ अपीलो का निस्तारण कर दिया गया है। मूल्य निर्धारण अपीलार्थी का एक न्यायिक कार्य था। हम इस स्थिति का विशेष उल्लेख करना चाहेंगे कि भले ही मूल्यांकन का निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के एक भाग के रूप में अपील में संशोधित या पुष्ट किया गया हो, फिर भी मामले की समग्र तस्वीर से न्यायिक अधिकारी का आचरण देखने के लिये उपलब्ध

होगा। उचित मामलों में यह न्यायिक कृत्यो से भी निष्कर्ष निकालने के लिए खुला हो सकता है, लेकिन वर्तमान मामले में जब तीन अपीलों में चुनौती नहीं दी गई थी और बाद में केवल तभी चुनौती दी गई जब मामला देखा गया, अपीलार्थी के रुख को स्वीकार किए जाने की कुछ गुंजाइश है कि कोई गलती हुई थी और कोई गलत मकसद नहीं था और वह संदेह के लाभ को पाने का हकदार है।

जहाँ तक रेफरेंसो पर पंचाट राशि जमा करने के लिय तीन महीनेकी समाप्ति से पहले भूमि अधिग्रहण अधिकारी को जारी किये गये अनुरोध पत्र कासवाल है, अपीलकर्ता के वकील ने बताया है कि भूमि मालिक मुआवजे का भुगतान करने के लिये बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और अपनी मांगो को मनवाने की चिंता में, अपीलार्थी ने भूमि अधिग्रहण अधिकारी के पास पडी मुआवजा राशि की वसूली के लिये अनुरोध करना उचित समझा। उनमें मुताबिक, यह एक अविवेकपूर्ण कार्य हो सकता है लेकिन वास्तव में अपीलार्थी की कार्रवाई के पीछे इसका कोई गलत उद्देश्य नहीं था और इसलिए उसे दंडित नहीं किया जाना चाहिए। स्पष्टीकरण स्वीकार करने के लिए बहुत सरल प्रतीत होता है लेकिन वकील के रुख को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह वास्तव में सरकार या भूमि अधिग्रहण अधिकारी के लिए खुला था कि वे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत प्रतिबंध की ओर इशारा करके अदालत को जवाब न दें। हमें बार में विद्वान महाधिवक्ता द्वारा बताया गया है जो प्रतिवादीगणो के रुख के समर्थन में पेश हुए थे, कि भूमि अधिग्रहण अधिकारी शायद नोटिस के अनुकूल प्रतिक्रिया के कार्य में एक सहमति देने वाला पक्ष था, लेकिन वह पहलू अपील के विस्तार के उद्देश्य से प्रासंगिक नहीं है। हमारे सामने रखी गई सामग्री के आधार पर, हमें नहीं लगता कि अपीलार्थी ने निर्दोष तरीके से काम किया।

अब हम मुद्रित ऑर्डर शीट के उपयोग के सवाल पर आते हैं, यह विवादित नहीं है कि ऑर्डर शीट न्यायालय में उपयोग के लिये निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराई जाती हैं और अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री एम. सी. येत्तिनमाता द्वारा मुद्रित ऑर्डर शीट का उपयोग करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी। आरोप के समर्थन में यह कहा गया कि यह विशेष अधिवक्ता अपीलार्थी के जिले से संबंधित है और जब वह बागलकोर में स्थानांतरित हो गया तो उसने अपीलकर्ता की अदालत में अपनी प्रैक्टिस को केंद्रित किया। इस आरोप से किसी उद्देश्य का आभास होता है और हम इस विशेषता पर ध्यान दे सकते हैं कि मानव स्वभाव जो है, वह है स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ चिंता। वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय आरोप के इस पहलू पर भरोसा करने में सही था। इस स्थिति को स्वीकार करते हुये कि अपीलकर्ता ने ऐसी ऑर्डरशीट का उपयोग करने की अनुमति देते समय अविवेकपूर्ण तरीके से काम किया था, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के खिलाफ सही पाया।

विद्वान महाधिवक्ता ने हमें उचित रूप से बताया है कि अपीलार्थी के पास लगभग 43 एकड़ कृषि भूमि है और इसलिए, वह इस बात से वे सहमत है कि इस बात पर कोई गंभीरता से विचार नहीं किया जा सकता है कि अपीलकर्ता ने एक पंप-सेट निर्धारित प्राधिकारी की बिना किसी पूर्व अनुमति के, जिसकी कीमत एक हजार रूपये थी, खरीदा था। हम विद्वान महाधिवक्ता से सहमत हैं।

इसलिए, अब विचार करने का प्रश्न यह है कि जब यह पाया जाता है कि अपीलकर्ता आरोपो के संदर्भ में दोषी था, तो क्या अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिये था। आम तौर पर, अनुशासनात्मक कार्रवाई में दी गई सजा की मात्रा का औचित्य तय करना अदालत का काम नहीं है और ऐसे मौके आये हैं जब इस अदालत ने सजा की मात्रा पर उच्च न्यायालयो के हस्तक्षेप को अधिकार क्षेत्र से बाहर

का कार्य माना है। यद्यपि हम उस तथ्य से अवगत हैं, आरोपों के अवशेषो को ध्यान में रखते हुए, हम यह मानने के इच्छुक हैं कि अपीलार्थी को सेवा से बर्खास्त करना अनुपाल से बाहर था और अनिवार्य सेवानिवृति न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी। हम तदनुसार निर्देश देते हैं कि बर्खास्तगी के स्थान पर, अपीलार्थी को बर्खास्तगी लागू होने की तारीख से सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त माना जाएगा । अपील विफल होती है और खारिज की जाती है। कोई लागत नहीं।

हम यह जोडना चाहेंगे कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि न्यायिक अधिकारियो को बोर्ड से उपर उठकर कार्य करना चाहिए और न्याय के चैनल को साफ रखना चाहिए। व्यवस्था में मुकदमेबाजी करने वाले पक्षों का विश्वास ही प्रणाली की नींव है और ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जिससे उस पर असर पडे ।

एन.पी.वी.

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।